भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2068

दिनांक 31 जुलाई, 2025 को उत्तरार्थ

.....

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के अंतर्गत निधि का आवंटन

2068. डॉ. थोल तिरूमावलवन:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) के अंतर्गत अब तक आवंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों को स्वच्छ करने के लिए कोई लक्ष्य तिथि निर्धारित की है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या इसके अंतर्गत कोई उपलब्धियाँ प्राप्त हुई हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री
(श्री राज भूषण चौधरी)

(क): भारत सरकार ने गंगा और उसकी सहायक नदियों के पुनरुद्धार के लिए वर्ष 2014-15 में नमामि गंगे कार्यक्रम (एनजीपी) शुरू किया था, जो पांच वर्षों के लिए मार्च 2021 तक था और इसे आगे बढ़ाकर मार्च 2026 तक कर दिया गया है।

नमामि गंगे कार्यक्रम के लिए वित्त वर्ष 2014-15 से वित्त वर्ष 2024-25 तक बजटीय आवंटन [संशोधित/अंतिम अनुमान (आरई)] 23,424.86 करोड़ रुपए था। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए बजट अनुमान (बीई) 3,400 करोड़ रुपए है। इस प्रकार, नमामि गंगे कार्यक्रम के लिए शुरुआत से लेकर वित्त वर्ष 2025-26 तक कुल बजटीय आवंटन 26,824.86 करोड़ रुपए है।

(ख) और (ग): नदी की सफाई एक सतत प्रक्रिया है और भारत सरकार नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करके गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों में प्रदूषण की चुनौतियों से निपटने में राज्य सरकारों के प्रयासों में सहायता कर रही है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत, गंगा और उसकी सहायक नदियों के पुनरुद्धार के लिए अपशिष्ट जल उपचार, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, नदी तट प्रबंधन (घाट और श्मशान घाट विकास), ई-प्रवाह, वनरोपण, जैव विविधता संरक्षण और जन भागीदारी आदि जैसे व्यापक उपाय किए गए हैं।

नमामि गंगे कार्यक्रम के अंतर्गत गंगा और उसकी सहायक नदियों के पुनरुद्धार के लिए कुल 502 परियोजनाएँ स्वीकृत की गई हैं। इनमें से 323 परियोजनाएँ पूरी हो चुकी हैं।

गंगा और उसकी सहायक नदियों की स्थिति में सुधार के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) की उपलब्धियां निम्नानुसार हैं:

i. रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2022 में किए गए मूल्यांकन वर्ष 2019 और वर्ष 2021 के आंकड़ों का उपयोग करके) के आधार पर गंगा नदी पर प्राथमिकता वाले नदी खंड (पीआरएस) निम्नानुसार हैं:

क. उत्तराखंड प्रदूषित खंडों में नहीं आता (बीओडी < 3 मिग्रा/ली);

ख. उत्तर प्रदेश में, फर्रुखाबाद से इलाहाबाद और मिर्जापुर से गाजीपुर तक के क्षेत्र प्राथमिकता वर्ग V (बीओडी 3-6 मिलीग्राम/लीटर) के अंतर्गत आते हैं;

ग. बिहार में, बक्सर, पटना, फतवा और भागलपुर के साथ वाले खंड प्राथमिकता वर्ग IV (बीओडी 6-10 मिलीग्राम/ली) के अंतर्गत आते हैं;

घ. झारखंड प्रदूषित खंडों में नहीं आता (बीओडी < 3 मिग्रा/ली);

ङ पश्चिम बंगाल में, बेहरामपुर से हल्दिया तक का खंड प्राथमिकता वर्ग IV (बीओडी 6-10 मिलीग्राम/लीटर) के अंतर्गत आता है।

इसके अलावा, घुलित ऑक्सीजन (डीओ) का मान, जो नदी की स्थिति का एक संकेतक है, अधिसूचित प्राथमिक स्नान जल गुणवत्ता मानदंडों की स्वीकार्य सीमा के भीतर पाया गया है और गंगा नदी के लगभग पूरे खंड में नदी के पारिस्थितिकी तंत्र को सहारा देने के लिए संतोषजनक है।

ii. **अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योगों (जीपीआई) के प्रदूषण भार में कमी:** आईआईटी और प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेजों जैसे तृतीय पक्ष के तकनीकी संस्थानों के माध्यम से जी.पी.आई. का वार्षिक निरीक्षण 2017 में शुरू हुआ। इसके परिणामस्वरूप बीओडी भार वर्ष 2017 में 26 टन प्रति दिन (टीपीडी) से घटकर वर्ष 2023 में 13.73 टीपीडी हो गया है, और अपशिष्ट प्रवाह में लगभग 28.6% की कमी आई है जो वर्ष 2017 में 349 एमएलडी से घटकर वर्ष 2023 में 249.31 एमएलडी हो गया है।

iii. वर्ष 2024-25 के दौरान गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे 50 स्थानों पर किए गए जैव-निगरानी के अनुसार, जैविक जल गुणवत्ता (बीडब्ल्यूक्यू) मुख्य रूप से 'अच्छी' से 'मध्यम' तक थी।

iv. इसके अलावा, पिछले एक दशक में गंगा नदी में डॉल्फ़िन की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वर्ष 2009 में 2,500-3,000 व्यक्तियों की अनुमानित आधार रेखा से, वर्ष 2015 में ये संख्या लगभग 3,500 हो गई और वर्ष 2021-2023 के दौरान किए गए राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण के अनुसार यह लगभग 6,327 तक पहुँच गई। यह 2009 से दोगुने से अधिक की वृद्धि को दर्शाता है। गंगा बेसिन में, 17 सहायक नदियों में वर्ष 2021-2023 के आकलन ने कई नदियों में डॉल्फ़िन की उपस्थिति की पुष्टि की, जहाँ पहले उनका रिकॉर्ड नहीं था, जैसे कि रूपनारायण, गिरवा, कौरियाला, बाबई, राप्ती, बागमती, महानंदा, केन, बेतवा और सिंध।

v. संयुक्त राष्ट्र (यूएन) ने भारत की पवित्र नदी गंगा के पुनरुद्धार हेतु नमामि गंगे पहल को प्राकृतिक जगत को पुनर्जीवित करने के लिए शीर्ष 10 वर्ल्ड रिस्टोरेशन डे फ्लैगशिप में से एक के रूप में मान्यता दी है। एनएमसीजी को यह पुरस्कार 14 दिसंबर 2022 को वर्ल्ड रिस्टोरेशन डे दिवस पर मॉन्ट्रियल, कनाडा में जैव विविधता सम्मेलन (सीबीडी) के 15वें सम्मेलन (सीओपी15) के एक समारोह में प्रदान किया गया।

*****